



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]
No. 211]भाई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2003/फाल्गुन 9, 1924
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2003/PHALGUNA 9, 1924

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

का.आ. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (V) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 319 (अ) तारीख 7 मई 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना में यथविर्विष्ट अरावली रेंज के विर्विष्ट क्षेत्र में कतिपय प्रक्रियाएं और संक्रियाएं, रिवाए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के, करने पर प्रतिषेध अधिरोपित किए गए थे;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त पूर्वोक्त शक्तियां, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1189 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 1999 द्वारा हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों को, प्रत्यायोजित कर दी थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 में अंतर्विष्ट विकास परियोजाओं के पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के उपबंधों के अधीन बड़े खनिजों, जिनमें पांच हैक्टेयर से अधिक के खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत हैं, के लिए खनन परियोजाओं को पर्यावरणीय आपति न होने की रवीकृति देने के लिए एक रूप प्रक्रिया होनी चाहिए;

और उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करना लोक हित में है वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 और का.आ. 319 (अ) तारीख 7 मई, 1992 में संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को अभिमुक्त करना लोक हित में है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्वक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

- पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 के पैरा 3 के मद (क) में "अनुसूची-1 को प्रविष्टि संख्या 3,18 और 20 शब्दों और अकों के स्थान पर" अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या 3 और 18 शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 319 (अ) तारीख 7 मई, 1992 में पैरा में I, मद (ii) के साथ पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी:-

खनन प्रक्रियाएं और संक्रियाएं पांच हैक्टेयर से अधिक के पट्टा क्षेत्रों वाली" खनन परियोजना (बड़े खनिज) को छोड़कर जिसमें निम्नतिखित है:-

- (क) सभी नई खनन संक्रियाएं जिसमें खनन पट्टों के नवीकरण भी हैं, या
- (ख) अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों और वाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्यमान खनन पट्टे, या
- (ग) सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना किया जा रहा खनन।

[फा. सं. जेड-12013/4/89-आई ए-1 (भाग)]
डॉ. चौ. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी 1 : विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण से संबंधित की मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 60 (अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इस संख्या का.आ. 356 (अ) तारीख 4 मई, 1994, का.आ. 318 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 1997, का.आ. 73 (अ) तारीख 27 जनवरी, 2000, का.आ. 119 (अ) तारीख 13 दिसम्बर 2000, का.आ. 737 (अ) तारीख 01 अगरत, 2001, का.आ. 1148 (अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 और का.आ. 632 (अ) तारीख 13 जून, 2002 द्वारा संशोधित की गई।

टिप्पणी 2 : अरावली रेज के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कतिपय क्रियाकलापों जिनसे क्षेत्र में पर्यावरणीय अवक्रमण हो रहा था को निपिद्ध करने की मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 319 (अ) तारीख 7 मई, 1992 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्या का.आ. 1189 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 1999 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2003

S.O. 248(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 319(E) dated the 7th May, 1992 (herein referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (herein referred to as the said Act) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (herein referred to as the said rules), the Central Government imposed prohibitions on carrying certain processes and operations in the specified areas of Aravalli range as specified in the said notification, except with prior permission of the Central Government.

And whereas, the Central Government had delegated the aforesaid powers conferred on it by the said notification, to the State Governments of Haryana and Rajasthan vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1189 (E) dated 29th November, 1999:

And whereas, the Central Government is of the opinion that there should be a uniform procedure for granting environmental clearance to mining projects for major minerals involving mining lease areas of more than five hectares under the provisions of the Environmental Impact Assessment of Development Projects contained in the notification of the Ministry of Environment and Forests number S.O. 60(E) dated 27th January, 1994:

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said rules provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the notifications of the Ministry of Environment and Forests numbers S.O. 60(E) dated 27th January 1994 and S.O. 319(E) dated 7th May 1992:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Act read with rule 5 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notifications with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette namely :-

1. In the notification of the Ministry of Environment and Forests number S.O. 60(E) dated 27th January, 1994, in paragraph 3, in item (a), for the words, figures and letter "nos.3, 18 and 20 of the Schedule-I", the words, figures and letter "numbers 3 and 18 of the Schedule-I" shall be substituted.

2. In the notification of the Ministry of Environment and Forests number S.O. 319(E) dated 7th May, 1992, in paragraph 1, for item (ii), the following item shall be substituted, namely :-

“(ii) Mining processes and operations, except mining project (major minerals) with lease areas of more than five hectares covering –

- (a) all new mining operations including renewals of mining leases, or
- (b) existing mining leases in sanctuaries or national park and areas covered under Project Tiger, or
- (c) mining is being done without permission of the competent authority.”

[F. No. Z-12013/4/89-IA- I (Part)]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Note 1: The principal notification relating to Environmental Impact Assessment of Development Projects was published in the Gazette of India vide number S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 and subsequently amended vide numbers S.O.356(E) dated the 4th May, 1994, S.O.318(E) dated 10th April, 1997, S.O.73(E) dated 27th January, 2000, S.O.119(E) dated the 13th December, 2000, S.O.737(E) dated the 1st August, 2001, S.O.1148(E) dated 21st November, 2001 and S.O.632(E) dated the 13th June, 2002.

Note 2: The principal notification restricting certain activities in specified area of Aravalli range which are causing environmental degradation in the region was published in the Gazette of India vide number S.O.319(E) dated the 7th May, 1992 and subsequently amended vide number S.O. 1189(E) dated the 29th November, 1999.